BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXV | 26th February 2014 | No. 4

आर.बी.आई के क्षेत्रीय निदेशक के साथ चैम्बर की बैठक

एक अप्रैल से हर बैंक बदलेंगे पुराने नोट – क्षेत्रीय निदेशक

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी दायीं ओर क्रमशः श्री मनोज कुमार वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, आर.बी.आई. एवं श्री प्रवीण कुमार, प्रबंधक, वैयक्तिक, आर.बी.आई. तथा बांयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, एवं कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं अन्य।

दिनांक 14.2.2014 को बिहार चैम्बर आफॅ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सभागार में भारतीय रिजर्व बैंक, पटना के क्षेत्रीय निदेशक, बिहार एवं झारखण्ड के साथ चैम्बर के सदस्यों की एक बैठक हुई जिसमें मुख्य मुद्दा यह था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2005 के पहले छपे नोटों को बदलने की घोषणा की है, इससे उत्पन्न अनेक भ्रान्तियों एवं कुछ हद तक भय के वातावरण को दूर करना।

क्षेत्रीय निदेशक, श्री मनोज कुमार वर्मा ने इस विषय पर बोलते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के इस कदम का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा से सम्बन्धित है। इसका Black & White से कोई स्म्बन्ध नहीं है। 2005 के पहले छपे नोटों में Security Features कुछ कम थे जिस वजह से उनकी नकल के नोट बाजार में काफी संख्या में आ रहे है और जिसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। 2005 के बाद के छपे नोटों में अनेक Security Features डाले गये हैं जिससे उन नोटों की नकल करना आसान नहीं है। इसलिए यह उचित समझा गया कि 2005 के पहले छपे सभी Denomination के नोट अर्थात् 1000 से 1 रुपये तक के सभी नोट बाजार से वापस ले लिये जाये। यद्यपि उन्होंने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि 30 जून के बाद भी 2005 के पूर्व छपे नोट जिन पर छपाई का वर्ष अंकित नहीं रहता है, वे भी Legal Tender बने रहेंगे और बाजार में चलेगे। उन्होंने कहा कि इन नोटों को बदलने की प्रक्रिया 1 अप्रैल, 2014 से प्रारम्भ होगी जिसके लिये सभी बैंक अपने यहाँ काउन्टर खोलेगें। नोटों को 30 जून, 2014 तक बदला जा सकेगा। तत्पश्चात् 1 जुलाई, 2014 से भी नोटों के बदलने की प्रक्रिया जारी रहेगी परन्तु इस शर्त के साथ कि जिस ग्राहक का बैंक में खाता नहीं है वे 1000 या 500 के 10 नोट तक ही बदलवा पायेंगे। 10 नोटों से ज्यादा बदलवाने पर उन्हें अपना Identity Proof and Residential Proof देना पड़ेगा। जिन ग्राहकों का बैंक में खाता है उनके साथ यह शर्त भी नहीं होगी। परन्तु नोटों की राशि उनके खाते में जमा हो जायेगी उन्हें नगद भुगतान नहीं होगा।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि 1, 2 और 5 के नोटों को वापस न लिया जाये तो बेहतर होगा क्योंकि इनके साथ लोगों की धार्मिक भावनायें भी जुड़ी है। लोग पूजा-पाठ, त्योहार एवं उत्सव, शादी-विवाह आदि अवसरों पर 51, 101, 201, 251, 501, 1001 रुपये देना चाहते हैं जिसमें इन छोटे नोटों का प्रयोग होता है। वैसे भी उन्होंने कहा कि 1 और 2 के नोट तो अब छपने ही बन्द हो गये है जो कि कालक्रम में स्वयं ही बाजार में उपलब्ध नहीं होंगे। रिजर्व बैंक 5 रुपये के नोट छापता है परन्तु कम मात्र में। उन्होंने आग्रह किया कि यदि 1, 2 और 5 के नोट आवश्यकतानुसार छापे जाये तो उचित होगा।

क्षेत्रीय निदेशक ने यह भी कहा कि पूरे विश्व में ही पुराने नोटों को समय-समय

पर वापस लेने की प्रक्रिया चलती रहती है क्योंकि कागज के नोटों का जीवन सीमित (4 से 6 महीने) रहता है। नोट बाजार में चलते-चलते बिल्कुल गंदे, कटे-फटे हो जाते हैं जिससे काफी दिक्कत होती है। इसलिए रिजर्व बैंक की ''Clean Note Policy'' हमेशा से ही रही है। वैसे भी 2005 के पहले छपे नोटों को बदलने के लिए काफी लम्बा समय दिया गया है और चिंता की या भय की कोई बात नहीं है। इसी क्रम में उन्होंने यह भी बताया कि नोटों पर स्याही से लिखना या अन्य किसी प्रकार से गन्दा करना उचित नहीं है और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिये ताकि रिजर्व बैंक की Clean Note Policy का पालन हो सके। इसी उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने नोट की गड्डियों में पिन मारने की प्रथा को बन्द किया और अब उन पर एक टेप लगाया जाता है।

बिहार में कम CD Ratio के बारे में उन्होंने कहा कि इसका उन्हें भी बहुत दुख है क्योंकि वे स्वयं भी बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योगों की कमी इसका सबसे बड़ा कारण है। मूलभूत सुविधायें विकसित नहीं हुई है जिसके कारण उद्योगपति आकर्षित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बैंक ऋणों को नहीं लौटाये जाना और फलस्वरूप उनका NPA हो जाना कम CD Ratio का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इस स्थिति के चलते बैंक बिहार में ऋण देने में शंशाकित रहते हैं ।

क्षेत्रीय निदेशक ने इस बात की भी चर्चा की कि रिजर्व बैंक बाजार में सिक्कों की पर्याप्त उपलब्धता के लिये सभी सार्वजनिक स्थलों पर Vending Machine लगवाना चाहता है जिसके लिए Machine लगाने वाले को Machine की कीमत का 50% अनुदान के रूप में दिया जाता है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक Vending Machine लगावें तो उन्हें अच्छी आमदनी हो सकती है।

एक सदस्य ने यह कहा कि बैंकों में लिंक फेल्योर के कारण बहुत असुविधा होती है विशेषकर जब कोई चेक Enchashment के लिये डाला जाता है और उसी समय लिंक फेल हो गया तो उसे Dishonoured मानकर ग्राहक के खाते में दण्ड स्वरूप कुछ रकम डेविट कर दी जाती है जबकि इसमें ग्राहक का कोई दोष नहीं है क्योंकि ऐसा लिंक फेल्योर के कारण हुआ है। इसलिए उनका सुझाव था कि लिंक फेल्योर की स्थिति में बैंक द्वारा चेक को Dishonoured नहीं कर Hold करके रखना चाहिये और जब लिंक आवे तब उसका Enchashment होना चाहिए।

इस अवसर पर आर०बी०आई के प्रबन्धक (वैयक्तिक), चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री मोती लाल खेतान सहित चैम्बर के सदस्य तथा प्रेस एवं मीडियाकर्मी काफी संख्या में उपस्थित थे।

उपाध्यक्ष, श्री सुभाष कुमार पटवारी के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

बजट

2014-15 में क्या है खुशखबरी

क्या होगा सस्ता : मोटरसाइकिल, स्कूटर, छोटी कार, एसयूवी, वाणिज्यिक वाहन, मोबाइल हैंडसेट, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, प्रिंटर, हाई डिस्क होगे सस्ते। साबुन और रंगीन रसायनों के भी घटेंगे दाम।

सेवा कर में राहत : ब्लड बैंक और कॉर्ड ब्लड बैंकों को सेवा कर के दायरे से किया बाहर। चावल के भंडारण, लदान, पैकिंग और भंडारगृह को भी सेवा कर से छूट का प्रस्ताव।

निर्माण क्षेत्र पर इनायत : सड़क निर्माण और मशीनरी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आयातित मशीनरी पर सीवीडी छूट समाप्त। **किसानों को कर्ज के ब्याज** में 2 फीसदी की छूट रहेगी जारी। 31 मार्च 2009 से पहले लिए गए शिक्षा ऋण के ब्याज की वसूली पर स्थगन।

• **कर में नहीं मिली राहत :** कर ढांचे में वित्त मंत्री ने नहीं की कोई छेड़छाड़, आम आदमी को आयकर में नहीं दी कोई राहत, 1 करोड़ रुपये से अधिक की सालाना आय वाले धनाढ्य व्यक्तियों पर 10 फीसदी अधिभार रहेगा जारी।

• **शुल्क में थोड़ी रियायत :** छोटी कारों, मोटरसाइकिलों और वाणिज्यिक पदार्थों पर उत्पाद शुल्क 12 फीसदी से घटाकर 8 फीसदी किया। एसयूवी पर भी घटा उत्पाद शुल्क • पूंजीगत वस्तुओं एवं कंज्यूट डययूरेबल्स पर उत्पाद शुल्क 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने का ऐलान।

अंतरिम बजट 2014-15 की मुख्य बातें

• वित्त वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा 4.6 फीसदी रहने का अनुमान, अगले वित्त वर्ष 4.1 फीसदी रहने का अनुमान • 2013-14 की तीसरी और चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 5.2 फीसदी रहने का अनुमान • चालू खाते का घाटा चालू वित्त वर्ष में 4,500 करोड़ डॉलर रहेगा • 2014-15 में योजनागत खर्च 5. 55 लाख करोड़ रुपये और गैर योजनागत खर्च 12.08 लाख करोड रुपये रहने का अनुमान • चालू वित्त वर्ष में विनिवेश लक्ष्य 40, 000 करोड़ रुपये से घटाकर 16,027 करोड़ रुपये किया। • सेना के लिए वन रैंक, वन पेंशन प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी • अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए बनेगा 200 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी कोष • महिलाओं की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए गठित निर्भया कोष के लिए 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन • समुदाय रेडियो स्टेशनों को प्रोत्साहित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 11.200 करोड़ रुपये का होगा निवेश।

(साभार: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 18.2.2014)

केन्द्रीय अंतरिम बजट से बिहार को निराशा

बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश अंतरिम आम बजट में बिहार को नजरअंदाज करने पर असंतोष प्रकट किया है। चैंबर अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि बिहारवासी आशान्वित थे कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने के संबंध में कुछ घोषणा की जायेगी। लेकिन इस बार भी निराशा हाथ लगी है। राज्य के विकास के लिए अपेक्षित विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिये जाने के बावजूद भी अन्य कोई विशेष योजना या विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गयी है। आयकर की छूट सीमा को बढ़ा कर कम-से-कम तीन लाख रुपये किया जायेगा, लेकिन इस संबंध में भी बजट में कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने बड़े एवं मध्यम कार, छोटे कार एवं ट् व्हीलर तथा वाणिज्यिक वाहनों के उत्पाद शुल्क में कटौती का स्वागत किया है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। साथ ही यह निर्भया फंड नन लेपसेबल होगा,जो स्वागतयोग्य है। उत्तर पूर्व राज्यों के विकास के लिए 1,200 करोड़ रुपये की व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में पूंजी आधार बढ़ाने के लिए 11,200 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी स्वागत योग्य है। शिक्षा लोन चुकाने के लिए मॉरोटरियल अवधि को बढ़ाने का निर्णय भी अच्छा है। **– पी० के० अग्रवाल,** अध्यक्ष, बीसीसीआई

(साभार : प्रभात खबर, 18.2.2014)

रेल-बजट -2014-15

• रेलवे मिनिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12.2.2014 को संसद में पेश किया इंटरिग रेल बजट • यात्री और माल भाड़े में नहीं हुई बढ़ोत्तरी, 17 प्रीमियम एसी ट्रेन समेत कुल 72 ट्रेनों का ऐलान • मोबाइल से टिकट बुकिंग, पीएनआर सिस्टम अपडेशन और रेल टैरिफ अथॉरिटी की स्थापना का भी ऐलान • रेलवे मिनिस्टर ने रेल बजट पेश करते हुए गिनाए यूपीए गवर्नमेंट के बीते दस सालों के अचीवमेंट्स।

बजट में खास : • यात्री किराए और माल ढुलाई दर में कोई बदलाव नहीं किया गया • 19 नई रेल लाइन का सर्वे कर उन्हें रेल सेवाओं से जोड़ा जाएगा • अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा • 10 नई पैसेंजर ट्रेन, 4 मेमू और 3 डेमू ट्रेनें चलाई गई • 3-3 ट्रेनों के फेरे और रूट बढ़ाए गए • शिलांग को इसी साल रेल लाइन से जोड़ा जाएगा • वैष्णो देवी के लिए जल्द रेल सेवा शुरू होगी • ईटानगर को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 2702 किसी नई रेल लाइन पर काम होगा • रेल किराए को तय करने के लिए बनी अथॉरिटी • रेल

अथॉरिटी तय करेगी कि किराया बढ़े या नहीं • 2500 सवारी डिब्बों में बायो-टॉयलेट की व्यवस्था, जिसे और बढ़ाया जाएगा • रेल पहिया कारखाना छपरा, रेल कोच फैक्टरी राय बरेली और डीजल कलपुर्जा कारखाना दानकुनी में प्रोजक्शन शुरू करना।

प्रीमियम ट्रेनों से आपको क्या होगा फायदा? : • प्रीमियम ट्रेनों में सीटों के किराए उनकी डिमांड के हिसाब से तय होते हैं। इसके टिकट सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ही मिलेंगे • इस स्कीम के तहत जो ट्रेनें चलेंगी उसका रिजर्वेशन 15 दिन पहले शुरु होगा • कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगी और न ही कोई तत्काल कोटा या लेडीज कोटा होगा • टिकट ऑनलाइन मिलने से दलालों के झमेले से बचेंगे • कंफर्म टिकट मिलेगा, फेस्टिव सीजन में टिकटों को लेकर होने वाली मारामारी से बचेंगे • दूरंतो की तर्ज पर नान स्टॉप चलेगी प्रीमियम एसी ट्रेन • शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से बेहतर सुविधाएं मिलेगी • खाने के मैन्यू में होंगे ज्यादा ऑप्शन।

(Sourer : I next, 13.2.2014)

परियोजनाओं को नहीं मिला धन

लालू प्रसाद के रेलमंत्रित्व काल में बिहार को कई बड़ी रेल परियोजनाएं मिली थी, मगर राशि के अभाव में यह परियोजनाएं लगभग बंद पड़ी है। सिर्फ छपरा रेल चक्का कारखाने में ही उत्पादन शुरू हो पाया है। मढौरा का डीजल लोकोमेटिव फैक्ट्री, सोनपुर का गुड्स वैगन रिपेयरिग वर्कशॉप व डीएमयू मेंटेनेंस डिपो, मधेपुरा का विद्युत लोकोमेटिव फैक्ट्री, डालमिया नगर के बोगी एवं कपलिंग फैक्ट्री और समस्तीपुर के वर्क्स शॉप एवं लोको शेड़ विस्तार का काम भी पैसे के कारण ही लटका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के हरनौत में बन रहे कोच मेंटेनंस वर्कशॉप का भी लगभग यही हाल है। इन परियोजनाओं के रफ्तार पकड़ने पर स्थानीय लोगों को काफी लाभ होता।

इन ट्रेनों के फेरे नहीं बढ़े : बिहार की तरफ से सांसदो-विधायकों ने नयी ट्रेनों के साथ ही कई पुराने ट्रेनों के फेरे बढ़ाये जाने की मांग भी की थी। इनमें पटना-पूरी एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन से बढ़ा कर तीन दिन करने, पटना-जम्मू अर्चना एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन के स्थान पर तीन दिन चलाने, पटना-अजमेर जियारत एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन से बढ़ा कर तीन दिन करने, पटना-अहमदाबाद अजीमाबाद एक्साप्रेस को सप्ताह में दो दिन से बढ़ा कर तीन दिन करने, इंदौर-पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन से तीन दिन किये जाने व दिल्ली-भभुआ गरीब रथ एक्सप्रेस को धनबाद तक विस्तार दिये जाने की मांग थी। मगर एक भी मांग पूरी नहीं हो सकी।

मेगा पुलों पर भी निर्णय नहीं : बिहार के विभित्र हिस्सों को जोड़ने के लिए पटना, मुगेर और कोशी में तीन मेगा पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। राशि का आवंटन नहीं होने से इनके पूरा होने में विलंब हो रहा है। इन परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने स्तर से राशि उपलब्ध करायी है।

पिछले साल मिली थीं नौ ट्रेनें : पिछले रेल बजट में बिहार को चार एक्सप्रेस, चार पैसेंजर और एक इंटसिटी ट्रेन मिली थी। इनमें पटना से दो एक्सप्रेस ट्रेनों राजेंद्र नगर- तिनसुकिया (साप्ताहिक) और पाटलिपुत्र-बंगलुरू (साप्ताहिक) एक्सप्रेस का परिचालन पिछले साल ही शुरू हो गया। कटिहार से हावड़ा की एक्सप्रेस ट्रेन चार दिन पहले 08 फरवरी से शुरू की गयी। कोलकाता-सीतामढ़ी के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को ही कोलकाता तक विस्तारित कर दिया गया।

(साभार : प्रभात खबर, 13.2.2014)

अंतरिम रेल बजट में बिहार की अवहेलना : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने संसद में पेश अंतरिम रेल बजट पर बिहार के साथ किये गये उपेक्षित व्यवहार पर निराशा व्यक्त किया है। चैम्बर अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि आशा थी कि बिहार की नयी परियोजनाओं व यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस पहल किया जायेगा। इस रेल बजट में बिहार की अवहेलना की गयी है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा रही थी कि रेल ट्रैफिक को सुविधा जनक बनाने के लिए बक्सर से मोकामा के बीच तीसरी रेल लाइन निर्माण का प्रावधान किया जायेगा। परंतु दुर्भाग्यवश रेल बजट इस पर भी मौन है। रेल किराये में कोई वृद्धि नहीं किये जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे यात्रियों को काफी राहत मिली है।

(साभार : प्रभात खबर, 13.2.2014)

टेक्सेशन

आयकर शिकायतों को निपटाएगा विशेष सेल

टैक्स जमा करने के लिए लगाए जाएंगे अतिरिक्त काउंटर

आयकरदाताओं की शिकायत का निपटारा अब आयकर विशेष सेल करेगा। कोई भी करदाता अपनी शिकायत इस सेल में दर्ज करा सकता है। सेल में जो भी शिकायत दर्ज होगी उसका निपटारा प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के अंदर होगा।

कोई भी करदाता जिसका असेसमेंट करने के बाद भी टैक्स रिफंड नहीं हुआ या जिन करदाताओं के अपीलीय आदेश का पालन नहीं हुआ है वे सेल से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कई करदाताओं के आय की गणना कर ली गई है लेकिन वह गणना सही नहीं है या ब्याज अधिक लग रहा है तो वे भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिन करदाताओं का रिफंड नहीं लौटा है या रिफंड पर ब्याज नहीं मिला है या सर्च के दौरान जब्त की गई संपत्ति को लौटाया नहीं गया है तो वे भी सेल का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 16.2.2014)

31 मार्च तक सर्विस रिकार्ड ऑनलाइन करेगा आयकर विभाग

आयकर विभाग ने अपने दफ्तरों को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। 31 मार्च तक विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का सर्विस रिकार्ड ऑनलाइन हो जायेगा।

नई दिल्ली से आए मानव संसाधन के अपर आयुक्त निखिल चौधरी व टीसीएस कंपनी के टीम लीडर ने नोडल अधिकाररियों को नए सॉफ्टवेयर पर काम करने के तरीकों से अवगत कराया। दोपहर 12.30 बजे से करीब 3 घंटों तक प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों से आए दो दर्जन नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। ये अधिकारी बाद में अपने दूसरे सहयोगियों को नए सॉफ्टवेयर पर काम करने का प्रशिक्षण देंगे। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारियों की छुट्टी, वेतनवृद्धि, कटौती के साथ वार्षिक गोपनीय चारित्री ऑनलाइन दर्ज की जायेगी। बताते चलें कि अगले वर्ष तक केन्द्र सरकार ने आयकर व डाक विभाग को पेपरलेस बनाने का फैसला लियाा है।

(साभार: दैनिक जागरण, 11.2.2014)

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से किसे छूट है ?

जिन लोगों की सालाना आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है और यह केवल वेतन से आती है तथा बैंक बचत खाते में दस हजार से अधिक की ब्याज आय नहीं है। ऐसे लोगों को आयकर का रिटर्न फाइल करने से छूट है। लेकिन यह छूट तभी मिलेगी जब उनकी टैक्स देनदारी की राशि स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस के रूप में नियोक्ता द्वारा काटकर सरकारी खाते में जमा कर दी हो।

उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 4.90 लाख रुपये है। उसे बचत खाते पर सालाना दस हजार की ब्याज आय होती है। ऐसा व्यक्ति रिटर्न फाइल करने से मुक्त है, क्योंकि उसकी कुछ आय पांच लाख से अधिक नहीं है। साथ ही, किसी व्यक्ति की कुल आय पांच लाख रुपये है और उसे ब्याज पर आय नहीं है तो उसके लिए भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है।

किसी की कुल सालाना आय 5.50 लाख रुपये है। उसे सालाना बचत खाते पर 8,000 रुपये की ब्याज आय होती है(इस पर टैक्स कटौती की जा चुकी है)। लेकिन यह व्यक्ति 80 सी के तहत किए गए निवेश पर 70, 000 रुपये की टैक्स छूट लेता है। इन स्थितियों में भी रिटर्न फाइल करने से छूट मिल सकती है। कुल सालाना आय 6.10 लाख और 10,000 रुपये की ब्याज आय (जिस पर टीडीएस कट चुका हो) होने पर अगर आप 80 सी के तहत एक लाख रूपये की, इंफ्रास्ट्रक्चर बांड में 20 हजार रुपये और मेडिकल इंश्योरेंस पर 15 हजार रुपये निवेश कर टैक्स छूट लेते हैं तो भी आपको रिटर्न फाइल करने की आवश्वकता नहीं होगी।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 10.2.2014)

5 लाख की जमीन रजिस्ट्री को पैन कार्ड जरूरी

आयकर विभाग रख रही है नजर

शहरी क्षेत्र में 5 लाख से अधिक को जमीन की रजिस्ट्री के लिए पैनकार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 30 लाख या उससे अधिक की किसी

संपत्ति की रजिस्ट्री की पूरी रिपोर्ट आयकर विभाग को भेजी जा रही है। पैनकाई की अनिवार्यता की सूचना सभी निंबधन कार्यालयों को भेज दी गई है। इसका मुख्य मकसद ब्लैक मनी पर अंकुश लगाना है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 10.2.2014)**

आईटी रिटर्न नहीं भरने वाले लोगों को नोटिस भेजेगा आयकर विभाग

वसूली का प्रयास : अधिकारी ने कहा, हम बड़े चूककर्ताओं से मार्च तक कर वसूलने का प्रयास करेंगे। हम संबधित आयकर अधिकारियों को रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों तथा रिटर्न जमा करना बंद करने वालों के बारें में विस्तृत ब्योरा देंगे। आयकर विभाग 2.45 लाख मामलों में पहले ही पत्र जारी कर चुका है।

अधिक खर्च करनेवाले लोग कर जांच के दायरे में : देश में अधिक खर्च करनेवाले 40.72 लाख से अधिक लोग आयकर विभाग की निगरानी के दायरे में हैं। आंकडों के अनुसार, विभाग के पास 40, 72,829 व्यक्तियों की जानकारी है जिन्होंने मौजूदा वित्त वर्ष में अपने बचत बैंक खातों में 10 लाख रुपए या इससे अधिक की नकदी जमा कराई। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, विभाग के पास उपलब्ध तकनीकी समाधानों के चलते अधिकारियों के पास काफी सूचनाएं तैयार हैं। हम तो केवल यह संदेश देना चाहता हैं कि कुछ भी गुप्त नहीं है। विभाग के पास जो जानकारी है उनमें दो लाख रुपए या अधिक मूल्य की म्युच्युअल फंड इकाइयां खरीदनेवाले, पाँच लाख रु या अधिक राशि के बांड या डिबेंचर खरीदने वाले, कंपनियों द्वारा जारी एक लाख रुपए या अधिक राशि के शेयरों के धारक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पांच लाख रु या अधिक राशि के बांड के धारक शामिल हैं। ऐसे लोगों की संख्या 40,40,396 है। **(साभार: दैनिक जगरण, 17.2.2014)**

अवैध रूप से सामान ढोया तो पकड़े जाएंगे गाड़ी वाले

महात्मा गांधी सेतु के रास्ते अवैध रूप से सामान ढोने वाले वाहन चालक अब पकडे जाएंगे। वाणिज्य कर विभाग ने पुल पर अस्थाई चेकपोस्ट बनाया है। यह हाजीपुर टोल प्लाजा के पास है। इससे टैक्स चोरी पर लगाम लग सकेगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.2.2014)

बस पर व्यापारियों का सामान ढोया तो कार्रवाई

अगर आप बस ऑपरेटर हैं और अपने बस पर किसी व्यापारी के सामान का परिवहन करते हैं तो इसे जल्द ही बंद कर दें। पकड़े जाने पर उस व्यापारी पर कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही बस का परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा। इस बारे में वाणिज्य कर विभाग ने आदेश निकाल दिया है। वाणिज्य कर विभाग ने 25 वैसे बसों की सूची परिवहन विभाग को परमिट रद्द करने की भेज दिया है। एक-दो दिनों के अंदर 25 और बसों की सूची परिवहन विभाग को भेज दी जाएगी।

दोबारा पकड़े जाने पर एफआईआर : अगर कोई बस दोबारा ऐसी गलती करते पकड़ा जाता है तो विभाग सीधे बस मालिक के साथ-साथ ड्राइवर, कंडक्टर पर भी प्राथमिकी दर्ज करेगा।

क्या कहना है विभाग का : वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव एन. के. सिन्हा ने बताया कि किसी बस से व्यापारियों के सामान का परिवहन करना गैर कानूनी है। बस में केवल यात्रियों का सामान ही होना चाहिए।

सभी चेकपोस्ट पर कार्रवाई शुरू : विभाग ने अपने सभी चेकपोस्ट के पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि अगर किसी बस में इस तरह की सूचना मिलती है तो उस बस पर लदे सामान की जांच की जाए। धावा दल के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे भी इस तरह की सूचना मिलने पर उचित कार्रवाई करें।

क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट फेडरेशन : बिहार राज्य मोटर ट्रांसापोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग का यह निर्णय उचित नहीं है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.2.2014)**

झारखंड : कलपुर्जों पर घटेगा वैट!

झारखंड में वाहनों के कलपुर्जे बनाने वाली एक हजार से अधिक छोटी बड़ी औघोगिक इकाइयों को 14 फीसदी के भारी भरकम मूल्य वर्धित कर से बहुत हद तक निजात मिलने की उम्मीद है। राज्य की ऐसी इकाइयों में करीब 950 इकाइयां अकेले जमशेदपुर के निकट आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं। इन इकाइयों में टाटा मोटर्स के भारी वाहन संयत्र तथा इससे जुड़े कुछ अन्य संयंत्रों में बनने वाले ट्रक, ट्रेलर, डंपर और अन्य मल्टी एक्सेल वाहनों तथा संबंधित उपकरणों के लिए कल पुर्जे बनाए जाते हैं।

सिंहभूम चैंबर ऑफ कामर्स ऐंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सुरेश संथालिया ने बुधवार को बताया कि हाल में उद्यमियों ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह से मुलाकात की थी। इस दौरान वाहनों के कलपुर्जों पर मूल्य वर्धित कर को 14 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने पर मौखिक सहमति बनी है और सरकार इसके लिए संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए जल्द ही एक बैठक बुलाएगी। संथालिया ने बताया कि टाटा मोटर्स ममेत वाहन क्षेत्रों में आई मंदी का असर इससे जुड़ी सहायक इकाइयों पर भी पड़ी है। ऐसे में वैट में कमी होने पर इन इकाइयों को राहत मिलेगी। ज्ञातव्य है कि टाटा मोटर्स ने भी मूल्य वर्धित कर कम करने के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 13.2.2014)**

सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कम

बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में इसके औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2009 से 2012 के बीच लगातार बढ़ा है। लेकिन अभी भी राष्ट्रीय स्तर और अन्य राज्यों के मुकाबले इस मामले में बिहार काफी पीछे है। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद 2010-11 में 130.27, 2011-12 में 144.27 और 2012-13 में 165 करोड़ रुपए का था।

औद्योगिक क्षेत्र का सकत घरेल् उत्पाद में योगदान (% में)

राज्य	09-10	10-11	11-12
बिहार	18.8	19.8	20.7
उत्तर प्रदेश	24.5	24.2	23.4
महाराष्ट्र	30.9	30.8	31
गुजरात	41.5	41.1	41.1
हरियाणा	30.4	29.6	29
झारखंड	40.1	39.1	38.1
आंध्रप्रदेश	26	25.9	25.7
कर्नाटक	29.7	29.4	28.8
भारत	28.3	28.2	27.5

विकास के साथ-साथ बढ़ा बैंकों का भेदभाव

नियमों को आसान बनाकर बिहार को अधिक कर्ज देने का सुझाव

बिहार में विकास की गति बढ़ने के साथ-साथ बैंकों का भेदभाव भी बढ़ता जा रहा है। राज्य के बैंकों में यहां के लोगों ने 165209 करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं। इसकी तुलना में बैंकों ने अब तक मात्र 49735 करोड़ रुपए कर्ज दिए।

मतलब बैक शाखाओं में जमा 115474 करोड़ रुपए का हमारे विकास में योगदान की बजाए, दूसरे प्रदेशों की समृद्धि बढाने में उपयोग हो रहा है। राज्य के बैंकों में प्रति व्यक्ति 15215 रुपए जमा है। इसकी तुलना में बैंकों ने प्रति व्यक्ति 4580 रुपए का कर्ज बांटा। नतीजा प्रति व्यक्ति 10635 रुपए से सिर्फ बैंकों का कारोबार चमक रहा है। बिहार के साथ बैंकों के भेदभाव को ताजा आर्थिक सर्वेक्षण में उजागर किया गया है। रिपोर्ट में बिहार में कार्यरत बैंकों से अधिक शाखाएं खोलने और कर्ज मानकों को आसान बनाकर अधिक से अधिक कर्ज देने की आवश्यकता जताई गई है।

बैंकों में जमा धन और कर्ज का हाल

राज्य	कुल जमा (करोड़)	कर्ज (कराड़े)	प्रति व्यक्ति जमा (रु.)	प्रतिव्यक्ति कर्ज (रु)
महाराष्ट्र	1785043	1576489	154165	136154
तमिलनाडु	446577	549245	60079	73892
कर्नाटक	464639	331540	73794	52655
आंध्रप्रदेश	398497	438107	46029	50604
गुजरात	361054	260642	57716	41664
केरल	234217	171712	69487	50943
पंजाब	200680	162550	70556	57150

राजस्थान	177139	163268	24828	22883
हरियाण	169911	129274	64591	49143
बिहार	165209	48735	15215	4580

राजकीय वित्त व्यवस्था : • 2013-14 में राज्य का राजस्व अधिशेष 6809 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 2012-13 में 5101 करोड़ रूपये था • 2008-09 से 2012-13 के बीच सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर विकासमूलक राजस्व व्यय 17,078 करोड़ रुपये से बढ़कर 35,817 करोड़ रुपये हो गया। **(साभार : दैनिक भास्कर, 15.02.2014)**

चेक जमा करने के दिन ही खाते में आएगा पैसा

आरबी आई की पहल

बैंक और पोस्ट ऑफिस में चेक जमा करने के बाद क्लियरेंस के लिए अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पडेगा। आप जिस दिन चेक जमा करेंगे, उसी दिन उनके एकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा।

आरबी आई ने सभी बैंकों और पोस्ट ऑफिस को 28 फरवरी तक चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) मशीन बैठाने का निर्देश दिया है। कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ने सभी बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधियों की बैठक में इस संबंध में दिशा-निर्देश दिया था। इस मशीन के जरिए उपभोक्ताओं का चेक जिस दिन जमा होगा, उसी दिन उनका पैसा एकाउंट में जमा हो जाएगा। दिल्ली में स्थापित नॉर्दर्न ग्रिड के जरिए यह सुविधा लोगों को मिल सकेगी।

अभी यह है स्थिति : अभी चेक क्लियरेंस में तीन से चार दिन लगते हैं। त्योहार के मौसम में तो यह समय और ज्यादा हो जाता है। चेक को कंप्यूटर में अपटूडेट करने में समय लग जाता था। कंप्यूटर खराब होने या सर्वर डाउन रहने पर समस्या और विकट हो जाती है।

यहां लगेगी मशीन : राजधानी में जीपीओं व बांकीपुर पोस्ट ऑफिस समेत स्टेट बैंक, यूनियन बैक और पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में सीटीएस मशीन लगेगी।

तुरत मिलेगी सूचना : सीटीएस मशीन से इमेज के माध्यम से चेक की स्कैनिंग होगी, जिसके बाद डाटा सिस्टम में चला जाएगा। फिर नॉर्दर्न ग्रिड से इमेज के माध्यम से क्लियरेंस की सूचना मिल जाएगी।

"भारतीय रिजर्व बैंक ने सीटीएस मशीन लगाने का निर्देश दिया है। मशीन खरीदनें के लिए चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ब्रिगोडियर जी. भूयान को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। **–यू. सी. प्रसाद,** उपमुख्य डाकपाल जीपीओ

(साभार - हिन्दुस्तान, 15.2.2014)

अनुक्रमणिका

• 1. आयकर में छूट से सम्बन्धित विभित्र योजनाओं की जानकारी 05
• 2. आयकर लोकपाल .....12 • 3. इश्योरेंस पॉलिसी और उनके प्रीमियम 17
• 4. आयकर रिटर्न.....23 • 5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट-मोटर साईकिल चैन 26
• 6. नोटिफिकेशन और सर्कुलर .....32 **(साभार : टैक्स पत्रिका, जनवरी, 2014)**

इण्डस्ट्री

बगैर उद्योग के भी बाजार गुलजार

सुधर जाए व्यवस्था तो अभी दोगुना हो जाएगा आंकड़ा

गुंजाइश ही गुंजाइश : उद्योग के मामले में बिहार को भले पिछड़ा माना जाता हो, बाजार के मामले में यह कई मामले में शीर्ष पर है। बाजार के पंडितों का आंकलन है कि अगर व्यवस्था सुधर जाए तो कारोबार का दायरा सीधे दोगुना हो जाने की भी संभावना है।

पटना में बाजार की स्थिति : बाजार के दृष्टिकोण से यह बिहार का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण दो हैं। पहला यह कि पटना का विस्तार लगातार हुआ है। आबादी अब 19 लाख पर पहुंच चुकी है। आबादी के अनुरूप बाजार का दायरा बढ़ना स्वाभाविक है। यह आबादी उत्पादों के प्रति जागरुक भी हुई है, खास कर ब्रांड के प्रति। इससे हर सेगमेंट के बड़े ब्रांड भी पटना पहुंच चुके हैं। चाहे हीरा हो या फिर जूता चप्पल। कपड़ा हो या फिर इलेक्ट्रानिक्स गुड्स। दूसरी बड़ी बात यह कि पटना पूरे बिहार का आपूर्तिकर्ता भी है। यहीं से अन्य जिलों के थोक, खुदरा विक्रेता खरीदारी करते है। इसलिए यह बिहार का सबसे बड़ा मार्केट है। जानकारों का मानना है कि किसी भी सेगमेंट की कुल वार्षिक बिक्री में पटना की हिस्सेदारी 40 से 60 फीसद होती है।

आबादी के अनुरूप बाजार का दायरा : आबादी के अनुरूप बाजार का दायरा बढ़ा है। हर सेगमेंट का विकास हुआ है, भले प्रतिशत अलग अलग है। आम तौर पर राष्ट्रीय ग्रोथ रेट के आसपास ही बिहार का भी ग्रोथ रेट है। कई सेगमेंट में यह आगे भी निकल चुका है। इसमें सीमेंट, मोबाइल फोन, ट्रेक्टर, कार जैसे उत्पादों का नाम लिया जा सकता है।

बाजार को प्रभावित करने वाले कारक : बाजार पर सबसे प्रतिकूल असर कामर्शियल टैक्स और प्रशासनिक व्यवस्था डाल रही है। सही व्यवसाय करने वाले टैक्स और छापेमारी से परेशान हैं, वहीं बिना कागज व्यापार करने वाले चांदी काट रहे हैं। वे अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उत्पाद उपलब्ध करा देते हैं।

"कामर्शियल टैक्स और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो जाए तो बाजार का दायरा सीधे दोगुना हो जाएगा।"
– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कामर्य एंड इंडस्ट्रीज

(साभार : दैनिक जागरण, 12.2.2014)

192 औद्योगिक इकाइयों का निर्माण पूर्ण

राज्य में औद्योगिक निवेश के पक्ष में माहौल बनने की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अब तक 192 परियोजनाएं स्थाापित हुई हैं व 181 इकाइयों के प्रोजेक्ट का काम प्रगति पर है। इनमें 5678.19 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिसमें 10239 लोगों को नियोजित किया गया है। औद्योगिक एवं कृषि विकास में ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वर्ष तीन हजार मेगावाट एवं 2015 में चार हजार मेगावाट विद्युत आपूर्ति का लक्ष्य है। मुजफ्फरपुर की एक यूनिट में उत्पादन शुरू हो चुका है। दूसरे यूनिट से अक्तूबर 2014 से उत्पादन शुरु हो जायेगा। बरौनी ताप विद्युत प्रतिष्ठान के क्षमता विस्तार परियोजना के तहत 3668 करोड़ रुपये की लागत से 250 मेगावाट की दो नयी इकाई एवं मुजफ्फरपुर ताप विद्युत क्षमता विस्तार परियोजना के तहत 3345 करोड़ की लागत से 195 मेगावाट की दो इकाईयों का निर्माण कराया जायेगा। राज्य के 32 ऐसे राजस्व अनुमंडल हैं, जहां ग्रिड सब स्टेशन नहीं है। इन अनुमंडलों में 1800 करोड़ की लागत से ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जायेगा। सूखे से निबटने के लिए सरकार नदी जोड़ योजना कार्यान्वित कराया जाना है। राज्य के अंदर नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना के अंतर्गत बूढ़ी गंडक-नून-बाया- गंगा लिंक नहर का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजा है। इस पर 4214 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। **(साभार : प्रभात खबर, 15.2.2014)**

बिहार गरीबी मिटाने में नंबर-2

12 फीसदी के साथ बिहार ने देश में सर्वाधिक वृद्धि दर हासिल की है। 5.7 फीसदी वर्ष 2005-06 में स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद था।

विकास की गति बरकरार रखते हुए बिहार ने देश में सर्वाधिक 12 फीसदी वृद्धि दर हासिल की है। गरीबी कम करने में बिहार दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आय, कृषि उत्पादकता, औद्योगिक विकास, पर्यटकों का आगमन, सिंचाई क्षमता के सृजन और राजस्व जुटाने की कसौटी पर भी प्रदर्शन बेहतरीन रहा।

प्रति व्यक्ति आय में हुई बढोतरी

• कृषि उत्पादकता में भी इजाफा • औद्योगिक विकास की गति बढ़ी • पर्यटकों की आवाजाही में वृद्धि • सड़कों की लम्बाई में राष्ट्रीय औसत से आगे • साक्षरता बढ़ी, शिशु मृत्यु दर में कमी • छात्राओं का ड्रापआउट रेट घटा।

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के बार में यह जानकारी शुक्रवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में वित्त सचिव संजीव हंस और आर्थिक विशेषज्ञ और आद्री के सचिव शैबाल गुप्ता ने दी। श्री गुप्ता ने कहा कि यदि बिहार में विकास दर की यही गति रही तो राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में 20 साल लगेंगे। बिहार इसीलिए बड़े रिसोर्स की मांग कर रहा है, ताकि राज्य को इस गैप को पाटने में कम समय लगे। 2012-13 में विकास दर 14.48 है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा में जल संसाधन

मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 2013-14 के आर्थिक सर्वेक्षण को सदन पटल पर रखा।

अर्थ व्यवस्था का कायापलट : आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वर्ष 2006 से 2013 की अवधि में अर्थव्यवस्था का कायापलट हुआ। इसमें 12 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। यह देश के अधिकतम विकास दर वाले राज्यों में एक है। इससे पहले वर्ष 2005-06 में स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद महज 5.7 फीसदी था। **(साभार : हिन्दुस्तान, 15.2.2014)**

बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी

शैबाल गुप्ता ने बताया कि गरीबी दूर करने में ओडिशा के बाद बिहार दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रीय औसत 15.3 फीसदी के मुकाबले बिहार का औसत 20.7 रहा है। ग्रामीण और शहरी गरीबों का अनुपात भी कम हुआ है। राज्य सरकार ने यह उपलब्धि वर्ष 2004-05 से 2011-12 के बीच हासिल की है।

प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी : प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2012-13 में 30, 930 रुपए थी। वर्ष 2011-2012 में प्रति व्यक्ति आय जो संपूर्ण भारत के औसत का 37. 18 फीसदी थी, वर्ष 2012-13 में बढ़कर उसका 41.18 फीसदी हो गई।

निजी निवेश बढ़ने पर होगा तेज विकास : बिहार में अधिकतर कार्य सरकारी धन से हो रहा है। पब्लिक फाइनांस की जगह जब प्राइवेट फाइनांस बढ़ेगा तभी राज्य में तीव्र विकास होगा।

इन मोर्चों पर है चुनौती : औद्योगिक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 17.1 थी। वर्ष 2011-12 में विकास दर में गिरावट (9.5 फीसदी) दर्ज की गई। वर्ष 2012-13 में 17.1 फीसदी विकास दर के लिए सूबा इस चुनौती से उबरने के रास्ते पर है।

सतत विकास की प्रक्रिया को टिकाए रखने के लिए बिजली के क्षेत्र में काफी सुधार करना होगा। सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद बिहार सड़कों के मामले में राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है। इन मोर्चे पर सुधार की जरूरत है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अन्य मुख्य बिन्दु : • धान की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 2000 किलो से ऊपर • गेहूं का औसत वार्षि उत्पादन 61.74 लाख टन • वार्षिक मक्का उत्पादन 27.56 लाख टन की नई ऊंचाई पर • मछली उत्पादन वर्ष 2004-05 के 2.67 लाख टन से बढ़कर 4 लाख टन • कृषि-पशुपालन क्षेत्र में विकास दर 5.9 फीसदी रही • प्रति इकाई रोजगार 2.77 व्यक्ति से बढ़कर 4.06 व्यक्ति • वर्ष 2012-13 में समितियों से खरीदा गया दूध 12.45 लाख किग्रा • सितम्बर 2013 तक 2.83 लाख करोड़ के निवेश के 1362 प्रस्तावों को मंजूरी • प्रति इकाई निवेश 2007-08 के 1.87 लाख रुपए से बढ़कर 9.73 लाख • वर्ष 2007 के 1.8 लाख की तुलना में 2012 तक विदेशी पर्यटको की संख्या 11लाख • प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र के मामले में सड़कों की लम्बाई 192.73 कि.मी. (राष्ट्रीय औसत 142.67) • निर्बंधित वाहनों की संख्या 5 लाख (2007-08 में 1.62 लाख)।

बिहार का आठवां आर्थिक सर्वेक्षण : यह बिहार का आववां आर्थिक सर्वेक्षण है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी ने वित्त विभाग के सहयोग से बनाया है। उन्होंन कहा कि यह सर्वेक्षण खास तौर से वर्ष 2011-12 के आंकड़ों पर आधारित है। हालांकि इसमें 2012-13 और 2013-14 के सितम्बर तक के भी कुछ डाटा शामिल किए गए हैं। इस मौके पर आद्री के पी. पी. घोष और वित्तीय जानकार तिलकराज गौरी भी मौजूद थे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 15.2.2014)**

उद्योग और बुनकरों पर खास नजर

राज्य सरकार ने अगले साल के बजट में उद्योगों के साथ बुनकरों का भी खास खयाल रखा है। गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था की गई है। गन्ना विकास के सहयोगी खेती और डीजल अनुदान योजना को चालू रखने की व्यवस्था की है। साथ ही आठ नए चीनी मिलों को नया रूप सरकार देगी। इसके लिए उन्हें आईडा को सौंपा जाएगा।

फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में असीम संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने इस पर ध्यान केंद्रित किया, तो बिहार इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया। ब्रिटेनिया, पारले जी और रुचिसोया जैसी कंपनियों में उत्पादन शुरू हो गया है। सरकार ने इस बार फूड पार्कों को जमीन पर उतारने का मन बनाया है। मानसी में प्रीस्टिन मेगा फूड पार्क और बांका में जेवीएल मेगा फूड पार्क की स्थापना होगी। इसी के साथ बक्सर में भी एक नए फूड पार्क की योजना है। बुनकरों के समग्र विकास के लिए बनी योजना को अगले वर्ष भी जारी रखने का प्रस्ताव है। राज्य योजना मद से शुरू की गई इस योजना के तहत नया करघा और कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा देने के साथ कॉरपस मनी वर्कशॉप के निर्माण में भी सरकार सहायता देगी। खास बात यह है कि यह पैसा सीधे बुनकरों के खाते में डाला जाएगा। इससे बिचौलियों के लिए काई गुंजाइश नहीं रहेगी।

उद्योग जगत के लिए : • **821.34** करोड़ खर्च होंगे उद्योगों पर • **01** लाख टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज • **22** लाख टन मिलिंग क्षमता बढ़ेगी • **28** नई फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगेंगी • **150** करोड़ खर्च होंगे बुनकरों पर • **13525** हेक्टेयर में तसर की खेती • **2900** एकड़ में मनरेगा से लगेगा मलवरी पौधा • **487** लोगों को कीटपालन का प्रशिक्षण जाएगा।

उपलब्धियां : • **2516** इकाइयों को जमीन मिली • **1194** इकाइयों में उत्पादन शुरू • **146** इकाइयों को इस वर्ष मिली जमीन • **229** परियोजनाएं कार्यरत।

योजना : • आईडा को सौंपी जाएगी आठ चीनी मिलें • बांका और मानसी में बनेगा मेगा फुड पार्क • बक्सर में भी फूड पार्क बनाने की योजना।

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.2.2014)

आर्थिक सर्वेक्षण

जिलों में प्रति व्यक्ति आय

जिला	रुपया	पायदान
पटना	57843	1
नालंदा	10985	11
भोजपूर	11549	09
बक्सर	9741	20
रोहतास	12272	06
कैमूर	9549	23
गया	10414	17
जहानाबाद	9332	05
अरवल	8148	35
नवादा	8449	31
औरंगाबाद	9303	26
सारण	9588	22
सीवान	9200	27
गोपालगंज	10396	18
पश्चिम चंपारण	10586	16
पूर्वी चंपारण	8799	29
मुजफ्फरपुर	14097	05
सीतामढ़ी	8282	33
शिवहर	6209	38
वैशाली	11601	08
दरभंगा	10809	12
मधुबनी	10615	15
समस्तीपुर	10717	14
बेगूसराय	18447	03
मुंगेर	21019	02
शेखपुरा	8383	32
लखीसराय	11889	07
जमुई	9821	19
खगड़िया	9644	21
भागलपुर	15886	04
बांका	7764	37
सहरसा	11274	03
सुपौल	8202	03
मधेपुरा	8102	36
पूर्णिया	9365	24
किशनगंज	9135	28
अररिया	8542	30
कटिहार	10731	13

(साभार : प्रभाव खबर, 15.2.2014)

छोटे उद्योगों के उत्पाद को ब्रांड बनाएगी सरकार, बनेगा सुविधा केंद्र

राज्य के छोटे-छोटे उद्योगों में तैयार हो रहे उत्पाद ब्रांड के रूप में विकसित किए जाएंगे। सरकार इन उत्पादों की मैन्यूफैक्चरिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, आधुनिक तकनीक से उत्पादन के गुर सीखाएगी। इसके अलावा कच्चे माल की उपलब्धता के लिए डिपो तैयार करने व मार्केटिंग, डिजाइन केंद्र, जांच केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि की जानकारी दी जाएगी। ये सभी जानकारियां जिला व राज्य स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के उद्यमियों को प्रदान की जायेगी। छोटे उद्योगों के उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर के उत्पाद तैयार करने को लेकर प्रत्येक जिले में सामान्य सुविधा केंद्र के माध्यम से जानकारी दी जायेगी। इस केंद्र में बैंक परामर्शी से लेकर विभिन्न उद्यमों के ट्रेनर भी उपलब्ध होंगे। ट्रेनर की सुविधा उद्यमियों की मांग के अनुसार प्रदान की जायेगी। बेहतर प्रशिक्षण के लिए बड़े प्रशिक्षिण संस्थानों की जानकारी भी प्रदान की जाएगी।

अति लघु, लघु एवं मध्यम इकाइयों की वर्षवार स्थापना

वर्ष	मध्यम उद्योग	लघु उद्योग	अति लघु उद्योग	कुल
2006-07	--	1433	162063	163496
2007-08	04	42	7156	7202
2008-09	07	25	6122	6154
2009-10	02	41	5048	5091
2010-11	03	33	4799	4835
2011-12	02	56	4050	4108
2012-13(सितंबर)	05	09	1396	1410
कुल	23	1639	190634	192296

(साभार : हिन्दुस्तान, 7.2.2014)

सूबे के उद्योगों को अतिरिक्त वेटेज

सरकार के स्तर पर निर्माण या फिर होने वाली खरीद में बिहार की औद्योगिक इकाइयों और फर्मों को खास वेटेज दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी।

राज्य सरकार के स्तर पर क्रय या निर्माण से जुड़ी अगर निविदा निकाली जाती है तो उसमें सबसे कम दर कोट करने वाली कंपनी लोएस्ट वन कहलाती है। कार्यादेश उसे ही मिलता है। वित्त विभाग के नए प्रावधान के अनुसार निविदा में अगर बिहार की औद्योगिक इकाई शामिल है और उसके द्वारा कोट की गयी दर एलवन कंपनी से 15 प्रतिशत ज्यादा है तो उसे एलवन की जगह प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले से बिहार की इकाइयों को फायदा होगा।

तीन राइस मिलों को सरकार की मंजूरी

• कैमूर में दो और पूर्वी चंपारण में खुलेंगी एक • भोजपुर में पॉल्ट्री एंड कैटल फीड को भी सहमति।

सूबे में तीन राइस मिल को खोलने के लिए राज्य सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। कैमूर में दो और पूर्वी चंपारण में एक राइस मिल खोली जायेगी। वहीं, भोजपुर में पॉल्ट्री एंड कैटल फीड लगाने के लिए भी सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा। राइस मिल और पॉल्ट्री एंड कैटल फीड खुलने से बिहार में रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। इन उद्योगों को लगने से करीब 300-350 लोगों को रोजगार मिलेगा।

उद्योग	स्थान	लागत
मॉडर्न राइस मिल	खरौंदा, कैमूर	948.40 लाख
राइस मिल	मोहनिया, कैमूर	285.97 लाख
मॉडर्न पारा बॉयल्ड राइस मिल	रघुनाथपुर, पूर्वी चंपारण	1806.73 लाख
पॉल्ट्री एंड कैटल फीड	गिद्धा, भोजपुर	629.53 लाख

कैमूर के खरौंदा में आस्था इंडो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और कैमूर के ही मोहनिया में राजपूत एग्रो फूड प्रोडक्टेस कंपनी राइस मिल लगाने जा रही है। वहीं, पूर्वी चंपारण में मॉडर्न पारा बॉयल्ड राइस मिल खुलेगी। इसे जेके हाइटेक राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड स्थापित करेगा। कंपनियों ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। सरकार इन उद्योगों को लगाने के लिए 20 से 35 फीसदी तक की छूट भी देगी। फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए 35 फीसदी और सामान्य श्रेणी के उद्योगों के लिए 20 फीसदी राशि अनुदान के रूप में देती है। **(साभार: प्रभात खबर, 13.2.2014)**

बिहार के बक्सर में बनेगा फूड पार्क

बिहार सरकार ने बक्सर जिले में एक नया फूड पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। करीब 200 करोड़ रूपये लागत से बनने वाले इस फूड पार्क का निर्माण नई दिल्ली स्थित आम्रपाली समूह कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जाएंगी।

राज्य सरकार के कैबिनेट समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया, 'राज्य सरकार बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। इसी का नतीजा है कि अब राज्य में कई निवेशक भी आ रहे हैं। अब राज्य सरकार ने बक्सर जिले के नावानगर में एक फूड पार्क से संबंधित निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत 182.15 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित है। इस फूड पार्क में खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज और पशु आहार इकाइयां लगाई जाएंगी। इस फूड पार्क को राज्य सरकार अपनी खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत रियायतें भी मुहैया कराएगी।'

दरअसल, राज्य सरकार के नियमों के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से संबंधित सभी प्रस्तावों की मंजूरी राज्य कैबिनेट ही देती है। राज्य सरकार के मुताबिक इस फूड पार्क का निर्माण अगले दो-तीन सालों में किया जाएगा। इस परियोजना से करीब 5 हजार लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है।

करीब 32 एकड़ में फैले इस फूड पार्क का निर्माण आम्रपाली समूह की कंपनी, मम्स फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। कंपनी के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजीव कुमार सिंह ने बताया, इसके तहत हमने काम भी शुरू कर दिया है। इस वक्त इस फूड पार्क में दो इकाइयों ने काम भी शुरू कर दिया है। इसमें एक मक्का प्रसंस्करण से जुड़ी हुई है, जबकि दूसरी में कॉर्नफ्लक्स का उत्पादन हो रहा है। साथ ही, यहां आगे चलकर एक जूस उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की भी योजना है। हम यहां फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण की इकाई भी स्थापित करेंगे। इसके अलावा, हमारी योजना यहां एक पशु आहार की एक इकाई लगाने की भी है। हमारे इस फूड पार्क से इलाके के करीब 1 लाख लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे।

दूसरी तरफ, कंपनी ने यहां कच्चे माल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग (ठेके पर खेती) की शुरूआत भी की है। सिंह ने बताया, 'हमने कच्चे माल के लिए आस-पडोस के खेतों में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग की शुरुआत की है। इसके तहत हम अभी करीब एक हजार एकड़ खेत में खेती करवा रहे हैं।'

बढ़ रहा निवेश : • करीब 200 करोड़ रुपये लागत वाले इस पार्क का निर्माण करेगा दिल्ली का आम्रपाली समूह • फूड पार्क में खाद्य प्रसंस्करण कोल्ड स्टोरेज और पशु आहार इकाइयां लगाई जांएगी • इस फूड पार्क से इलाके के करीब 5 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 13.2.2014)**

आईएसआई मार्क के लिए सख्ती की तैयारी

बीआईएस ने बगैर आईएसआई मार्क के उत्पादों की बिक्री पर चिंता जताते हुए इसे रोकने की योजना बनाई है।

बगैर आईसआई मार्क के उत्पाद बनानेवालों पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) शिंकजा कसने जा रहा है। ऐसे 90 उत्पाद हैं, जिन पर बीआईएस का आईएसआई मार्क अनिवार्य है, लेकिन बाजार में अब भी ऐसे बहुत से उत्पाद हैं, जिनका उत्पादन बगैर आईएसआई मार्क के हो रहा है।

बीआईएस के महानिदेशक सुनील सोनी के मुताबिक, स्थापना से लेकर अभी तक देश भर में बीआईएस के 50,000 आईएसआई लाइसेंस जारी हुए हैं। उन्होंने बताया कि मार्च, 2015 तक बीआईएस ने आईएसआई लाइसेंस की संख्या को बढ़ाकर एक लाख करने का लक्ष्य रखा है। एक साल में आईएसआई लाइसेंस दोगुने करने के लिए बीआईएस राष्ट्रीय स्तर पर ताबड़तोड़ अभियान चलाने जा रहा है। इसके लिए उन सेक्टरों की पहचान की जाएगी, जहां उत्पादों पर आईएसआई मार्क अनिवार्य हो सकता है। इसके लिए बीआईएस गैर सरकारी संस्थाओं और सर्वे एजेंसियों की भी मदद लेगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 17.2.2014)**

सिंगल विंडो सिस्टम हो गया अप्रभावी

2006 में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की घोषणा की। कहा गया कि अब निवेशकों को सारी सहूलियतें एक ही जगह मिल जाएगी। उन्हें अलग-अलग कार्यालयों में नहीं भटकना पड़ेगा। निवेश तेज होगा। 31 अक्टूबर तक की सरकारी रिपोर्ट को आधार बनाए तो यह साबित हो रहा है कि हकीकत घोषणाओं से मीलों दूर है। 2.84 लाख करोड़ का निवेश होना था और हुआ महज 5,681 करोड़ रुपए का। इस समय तक कुल 1451 निवेश प्रस्ताव सिंगल विंडो कमिटी के सामने आए थे। इसके माध्यम से 2, 83,969 करोड़ रुपए निवेश की योजना था। लेकिन सिर्फ 90 परियोजना पर शुरू हुआ, जिसके कारण निवेश पांच हजार करोड़ तक आकर अटक गया।

स्वीकृति दे भूल जाती है प्रस्ताव : स्वीकृति दे देने के साथ ही सिंगल विंडो कमिटी अपने कार्य को पूरा मान लेती है। इसे निवेशकों की समस्याओं से लेना-देना नहीं होता और न ही समस्याओं के शीघ्र निष्पादन के लिए ही यह प्रयासरत होती है। प्रस्ताव के पूरी तरह लटकने पर ही सिंगल विंडो कमिटी सक्रिय होती है और जिम्मेदारों से जवाब तलब करती है। बैंक पर राज्य सरकारों का नियंत्रण नहीं होना भी बड़ा बाधा है। ज्यादातर निवेश प्रस्ताव बैंक लोन के भरोसे ही आते हैं जबकि बैंक इन्हें आसानी से लोन देन को तैयार नहीं होते।

प्रभावी बनता तो बढ़ता निवेश

इससे मंजूरी मिलने के बाद अन्य किसी से स्वीकृति की जरूरत नहीं पडती लेकिन यहां अन्य विभागों से स्वीकृति लेनी पड़ती है। प्रभावी हो तो इनवेस्टमेंट बढे। **– पी. के. अग्रवाल,** अध्यक्ष, बिहार चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंड्रस्टीज

समस्या ही समस्या

हम प्रस्तावों को स्वीकृति देने का संभव प्रयास करते हैं। किसी प्रस्ताव में कोई कभी भी होती है तो उसे अस्वीकृत करने की बजाए आवेदनकर्ता से वांछित सूचना मांगते हैं। सारे संबंधित विभाग बोर्ड के अधीन नहीं हैं इसलिए समस्या आती है।

– बी. एन. प्रसाद, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टरेट टेक्निकल डेक्लपमेंट, उ. वि.

और भी कई वजह हैं

निवेश प्रस्ताव को स्वीकृति देना सिंगल विंडो सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। निवेश के मार्ग में बाधा आने पर कमिटी संबंधित अधिकारी से बात कर मामले को सुलझाने का प्रयास करती है। निवेश कम होन के लिए कई अन्य करण भी जिम्मेदार हैं। **– रमेश कुमार,** उद्योग विस्तार पदाधिकारी, बिहार सरकार

एक मुश्त बिजली बिल देने पर सरचार्ज में 75 फीसदी छूट

पेसू 31 मई तक चलाएगा स्कीम : अगर बिजली बिल ज्यादा हो गया है तो सरचार्ज के नाम पर मोटी रकम नही चुकाना पड़ेगा। शर्त है कि एकमुश्त जमा करना होगा। यानी एक बार में बिल भरने पर सरचार्ज में 75 फीसदी तक की छूट मिलेगी। पेसू ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ओटीएस(वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम) स्कीम शुरू किया है। पहले बिल भुगतान के लिए इस तरह की सुविधा नहीं थी। 31 मई तक उपभोक्ता इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं।

फायदा क्या : डिले पेमेंट सरचार्ज से राहत मिल जाएगी। घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 75 फीसढ़ी और औद्योगिक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 50 फीसदी की छूट मिलेगी। जिनका बिजली कनेक्शन काट दिया गया है या जिनके ऊपर ज्यादा बकाया है। उन्हें भी इस स्फीम का लाभ मिलेगा।

1.5% मंथली इंटरेस्ट से भी राहत : पेसू के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता एसएसपी श्रीवास्तव ने बताया किइस योजना के तहत बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को हर महीने कुल बिजली बिल पर डेढ़ प्रतिशत ब्याज की भी छूट मिल जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी। बिल का रेगुलर भुगतान करना चाहिए।

(साभार : दैरिक भास्कर, 17.2.2014)

फिलहाल 4 शहरों में ही बिजली फ्रेंचाइजी पर

समीक्षा के बाद अन्य शहरों पर होगा निर्णय

राजधानी पटना और गया के बाद अन्य शहरों की बिजली को फ्रेंचाइची पर देने की योजना पर फिलहाल विराम लग जाएगा। पावर होल्डिंग कंपनी भविष्य में किसी शहर की बिजली व्यवस्था को फ्रेंचाइजी पर देने से पहले इन शहरों की समीक्षा करेगी, फिर कोई निर्णय लेगी।

भागलपुर और मुजफ्फरपुर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को पावर होल्डिंग कंपनी पहले ही निजी हाथों को सौंप चुकी है। वही, पटना और गया की बिजली माह के अंत तक फ्रेंचाइजी के हवाले हो जाएगी। इस समय राजधानी पटना को फ्रेंचाइजी पर देने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए मौजूदा प्रावधान में संशोधन किया जा रहा है। ताजा फैसले का असर आरा, बक्सर, दरभंगा और समस्तीपुर पर पड़ेगा। जिन्हें पावर होल्डिंग कंपनी फ्रेंचाइजी पर देने की योजना बना रही थी।

(विस्तृत : दैनिक जगरण, 17.2.2014)

Statement about ownership and other particulars about newspaper of the Bihar Chamber of Commerce & Industries Fortnightly Bulletin to be published in the first issue every year after last day of February.

Form - IV (See Rule 8)

1.	*Place of Publication*	:	*Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaughary Marg, Patna - 800001*
2.	*Periodicity of its publication*	:	*Fortnightly*
3.	*Printer's Name*	:	*A. K. Dubey*
	Whether citizen of India? (if foreigner, state the Country of origin)	:	*Indian*
	Address	:	*Asst. Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna -800001*
4.	*Publisher's Name*	:	*A. K. Dubey*
	Whether citizen of India? (If foreigner, state the Country of origin)	:	*Indian*
	Address	:	*Asst. Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna -800001*
5.	*Editor's Name*	:	*Shri A. K. P. Sinha*
	Whether citizen of India? (if foreigner, state the Country of origin)	:	*Indian*
	Address	:	*Natraj Engineers Pvt Ltd. 146, Patliputra, Patna - 800013*
6.	*Name and Address of Individual who own the newspaper and parterns of share holders*	:	*Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna -800001*

I, A. K. Dubey hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(A. K. Dubey)
Publisher

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296